

प्रिय,

जिनीता कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

शेरा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

राहरी विकास अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक-22 अक्टूबर, 2008

विषय : नगर पालिका परिषद, रामनगर के अन्तर्गत अवस्थापना विकास निधि से वित्तीय वर्ष-2005-06 में स्वीकृत कार्यों की अवशेष धनराशि की चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 में स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 471/V-श.वि-06-236(सा.)/2005, दिनांक 06.3.2006 के क्रम में शासनादेश संख्या 382/IV-श0वि0-07-236(सा0)/05 दिनांक 24-10-2007 तथा शासनादेश संख्या 239/IV(2)-श0वि0-08-236(सा0)/05 दिनांक 20-3-2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नगर पालिका परिषद, रामनगर जनपद नैनीताल के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के लिए ₹0-195.84 लाख के विपरीत क्रमशः ₹0 43.35 लाख, ₹0 40.00 लाख तथा 80.00 लाख अर्थात् कुल 163.35 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, रामनगर के पत्र संख्या 1227, दिनांक 30-8-2008 द्वारा प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार उक्त शासनादेश दिनांक 6-3-2006 द्वारा स्वीकृत कार्यों की धनराशि ₹0 146.76 लाख व्यय की जा चुकी है तथा ₹0 32.49 अवमुक्त किया जाना अवशेष है।

2- शासनादेश संख्या 278/V-श0वि0-06-236(सा0)/05 दिनांक 10-2-2006 तथा शासनादेश संख्या 2570/V/2006-236(सा0)/05 दिनांक 9-11-2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिनके माध्यम से क्रमशः ₹0 83.57 लाख तथा ₹0 1.46 लाख अर्थात् कुल 85.03 लाख धनराशि स्वीकृत की गयी थी उक्त के सम्प्रेष प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर कार्य पूर्ण करते हुए ₹0 75.68 लाख का व्यय किया गया है। इस प्रकार ₹0 9.35 लाख धनराशि बचत के रूप में अवशेष है।

3- अतएव उक्त के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 06-3-06 के माध्यम से स्वीकृत कार्यों के लिए स्वीकृति हेतु अब अवशेष ₹0-32.49 लाख के व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए इस धनराशि के विपरीत प्रस्तर-2 में उल्लिखित बचत/अवशेष की धनराशि ₹0 9.35 लाख का समायोजन करते हुए ₹. 23.14 लाख (रुपये तेईस लाख चौदह हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि ₹. 23.14 लाख (रुपये तेईस लाख चौदह हजार मात्र) आपके द्वारा आहरित कर सम्बन्धित नगर पालिका परिषद को बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंक के माध्यम से तब उपलब्ध करायी जायेगी, जब सम्बन्धित नगर पालिका परिषद यह स्पष्ट कर दे कि अनुमोदित लागत के विपरीत टेण्डर की लागत क्या है, स्पष्ट करने पर तदनुसार तथा शासनादेश की शर्त पूर्ण करने पर कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करेंगे।
2. शासनादेश संख्या 471/V-श.वि-06-236(सा.)/2005, दिनांक 06.3.2006, शासनादेश संख्या 278/V-श0वि0-06-236(सा0)/05 दिनांक 10-2-2006 में उल्लिखित अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में प्रस्तावित आगणतों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

4. सभी निर्माण कार्य समय-समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायें तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते हैं तो सम्बन्धित संस्था को अग्रोत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी।
5. कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
6. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
7. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनोदेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30 मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति के विवरण देने के बाद ही आगामी किस्त अदमुक्त की जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31-3-2009 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।

4- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 13 के अर्वाोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-03- छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-03-नगरों का समेकित विकास-05- नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास" के मानक मद '20 सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता' के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासित- 806/XXVII(2)/2008, दिनांक- 10 अक्टूबर, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विनीता कुमार)
प्रमुख सचिव।

सं०-12¹³ (1)/IV-शासित-08, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, महो मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
5. जिलाधिकारी, नैनीताल।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एनओआईसीओ, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जोओओ में इसे शामिल करें।
9. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रामनगर।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. ग्राहक बुक।

आज्ञा से,

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम)
अपर सचिव।